भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1086

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

1086. श्री संतोष कुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त मिशन के तहत अब तक कुल कितनी निधि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार का बिहार में गंगा नदी की तलहटी में जमा गाद को हटाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत गंगा और इसकी सहायक नदियों के पुनरूद्धार करने के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरूद्धार के लिए प्रदूषण के विभिन्न स्त्रोतों में सुधार हेतु प्रदूषण उपशमन उपायों जैसे नगरपालिका सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस कचरा, प्रदूषण के गैर-बिंदु स्त्रोत, और पारिस्थितिकी प्रवाह में सुधार करने के उपाय, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, नदी किनारों पर सुविधाओं में सुधार और साफ-सफाई, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, जन जागरूकता इत्यादि उपाय करने का एक व्यापक सेट शुरू किया गया है।

दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक, ₹38,438.05 करोड़ की अनुमानित लागत पर कुल 457 परियोजनाएं (सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं सहित) शुरू की गई है, जिनमें से 280 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है तथा परिचालित हो चुकी है। अधिकतर परियोजनाएं सीवेज के सृजन से संबंधित है क्योकि नदी में प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत अनुपचारित घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट जल है। 6,208.12 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) क्षमता के सृजन और पुनरूद्धार के लिए 31,575.84 करोड़ रूपए की लागत से कुल 198 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से, 111 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिसके फलस्वरूप 2,844.00 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन और पुनरूद्धार हुआ है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को ₹14,329.72 करोड़ जारी किए है। एनएमसीजी ने उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों को ₹ 13,735.40 करोड़ जारी/वितरित किए हैं, जिसमें से ₹13,286.84 करोड़ का उपयोग कर लिया गया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 31 दिसम्बर 2023 तक, भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को ₹ 2,131.93 करोड़ जारी किए गए है, जिसमें से विभिन्न एजेंसियों को ₹1,930.57 करोड़ जारी/वितरित किए गए है।

इस प्रकार, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत से (31 दिसम्बर 2023 तक) भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को ₹ 16,461.65 करोड़ जारी किए गए है, और एनएमसीजी द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 15,665.97 करोड़ जारी/वितरित किया है।

(ग) और (घ): केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारियों/अन्य मंत्रालयों द्वारा अवसाद के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए अवसाद प्रबंधन पर राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ, जलाशयों में अवसादन के प्रबंधन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 जून 2023 को सभी हितधारकों को नदियों एवं जलाशयों में अवसादन के वर्तमान मामलों के बारे में सभी हित धारकों को संवेदनशील बनाने के लिए अवसादन प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था।

*****